

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1177
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

मिड-डे-मील कार्यक्रम को माध्यमिक स्तर तक लागू किया जाना

1177. सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि भोजन अनेक अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने हेतु एक प्रोत्साहन है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए मिड-डे-मील कार्यक्रम को माध्यमिक स्तर तक लागू करने का विचार रखती है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ० डी. पुरंदेश्वरी)

(क): देश के विभिन्न भागों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि मध्याह्न भोजन योजना से नामांकन तथा उपस्थिति में वृद्धि हुई है जिससे प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तथापि, स्कूलों में छात्रों का नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कई कदमों, स्वास्थ्य तथा पोषण और आर्थिक विकास, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों, प्रारंभिक शिक्षा में निजी क्षेत्र के विस्तार इत्यादि पर भी निर्भर करता है।

(ख) और (ग): 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता संबंधी कार्य दल ने कक्षा IX और X में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना को समाविष्ट करने की सिफारिश की है। इसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल निधियों की आवश्यकता 21523 करोड़ रुपए आंकी गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप अभी दिया जाना है।